

महिला सशक्तिकरण के चरण

शोधार्थी – सुमन मीना

राजनीति विज्ञान विभाग,

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

महिलाओं को सशक्त बनाना आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है ताकि वे जान सकें कि कानून के द्वारा वे कौन-कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती हैं? अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती हैं?

संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकारी तथा दर्जा दिया गया है, समय समय पर और भी कानून बनाए गए हैं जिससे कानूनी दृष्टि से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है।

महिलाओं के प्रति पुलिस का व्यवहार

बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पुलिस के कार्य करने का तरीका कैसा है इसकी जानकारी हुई किसी भी अखबार और मीडिया से मिल जाएगी और बात जब महिलाओं के बारे में होतो कहना ही क्या आए दिन अपना मुह छुपाती हुई नजर आती है।

इन सबके लिए महिला पुलिस के साथ-साथ महिला उपराध प्रकोष्ठ बनाये गये हैं जिके द्वारा महिलाओं पर हो रहे अपराधों के त्वरित कार्यवाही कही जा रही है तथा अन्य कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं –

1. महिला पुलिस थानों की स्थापना।
2. महिला अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना।

3. महिला न्यायलायों की स्थापना ।
 4. महिला अभियोजकों की नियुक्ति
 5. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना ।
 6. महिला बटालियन का निर्माण ।
 7. महिला अपराधों से निपटने हेतु पुलिस प्रशासन में सुधार के सुझाव
1. पुलिसकर्मियों को महिला संबंधी कानूनों व अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशों की पूरी जानकारी नहीं है उन्हें कानून संबंधी ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है ।
 2. पुलिसकर्मियों में जो पुरुष प्रधान वाली पवृति है उसे बदलने की जरूरत है उसके लिए व्यापक कार्यवाही होनी चाहिए ।
 3. महिला थानों की संख्या बहुत कम है उनमें भी हवालात नहीं है तो महिला अभियुक्तों को उन्ह्य हवालातों में रखना पडता है । जिससे वही अपराध को बढ़ावा मिलता है ।
 4. महिला पुलिस को विशेष दस्ते बनाने जरूरी है जो कि विशेषज्ञ रूप से प्रषिक्षण लिए हुए हो और किसी भी आपात स्थिति का सामना कर सके ।
 5. महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा हेतु कडे से कडे कानून बनने चाहिए तथा उनकी कटाई से पालना करवानी चाहिए ।

महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाए –

क्र.सं	योजना का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष	योजना का मुख्य उद्देश्य
1.	डवाकरा योजना	1982	ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, स्वच्छता तथा शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाए प्रदान करना।
2.	न्यू मॉडल चर्खा योजना	1987	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रशिक्षण तथा अनुदान प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना।
3.	नौराड प्रशिक्षण योजना	1989	महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों जैसे दरी, चिकन, प्रिंटिंग आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर आर्थिक गतिविधियों से सलग्न करना।
4.	महिला समाख्या योजना	1989	स्वयं सहायता के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
5.	मातृ एवं शिशु स्वाय कार्यक्रम	1992	माता व शिशु को पोषाहार उपलब्ध कराना सुरक्षित मातृत्व तथा टीकाकरण आदि शिशु व मातृ मृत्यु में कमी लाना।
6.	किशोरी बालिका योजना	1992	गरीब बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा।
7.	महिला समृद्धि योजना	1993	ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डाल सशक्त बनाना।

8.	राष्ट्रीय महिला कोष	1993	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की में आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन हेतु उपलब्ध करा उनकी आया बढ़ाना।
9.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	1994	गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं को पसूति हेतु आर्थिक सहायता।
10.	इन्दिरा महिला योजना 1995	1995	गंदी बस्तियों की महिलाओं को आर्थिक स्वाबलबन
11.	मर्जिन मनी ऋण योजना	1995	महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बैंको से ऋण तथा मार्जिन मनी उपलब्ध कराना।
12.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना	1996	ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी वृद्धि जागरूक बनाना तथा भेदभाव समाप्त करना।
13.	राज राजेश्वरी बीमा योजना	1997	गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं महिलाओं को बिना किसी प्रीमीयम राशि पर विकलांगता की स्थिति में जीवन निर्वाह हेतु एकमुष्ट आर्थिक सहायता प्रदान करना।
14.	स्वास्थ्य सखी	1997	अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं को प्रजनन व बाल स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रशिक्षण प्रदान करना व आर्थिक लाभ प्रदान करना।
15.	बालिका समृद्धि योजना	1997	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की बालिकाओं की माता को पोष्टिक आहार तथा 10 वी तक बालिका की पढ़ाई हेतु नकद शैक्षिणा अनुदान सहायता प्रदान करना।

12 नवम्बर 1995 को राष्ट्रीय नीति का प्रारम्भिक प्रारूप जारी दिया इसमें –

1. महिलाओं की राजनैतिक निर्णय की प्रक्रिया में साझेदारी।
2. महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव समाप्त किया जाये।
3. महिलाओं के उत्थान हेतु समुचित मशीनरी का विकास।
4. महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति सूचना में बराबरी का अधिकार लिए आधारित जनगणना का विप्लेषण कर समाज में स्थापित कमियों को दूर किया जाये।